सत्यब्रत साहु, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव
मंत्रालय

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता

अ.शा. पत्र डब्ल्यू-11042/16/2010-जल-II
दिनांक: 01-12-2014

प्रिय,

जैसा कि आप जानते हैं, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय राज्यों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण जल सुरक्षा पायलट परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें 11 भिन्न राज्यों में 15 अत्यधिक दोहित खतरे में पड़े ब्लाकों के लिए ब्लॉक-वार जल सुरक्षा योजना तैयार की जाएगी। आपके राज्य के जिला अमरावती के वरुड और मोर्शी ब्लॉक भी इस पायलट परियोजना के अंश थे।

जून, 2014 से पायलट परियोजनाओं की समीक्षा के लिए 11 राज्यों के साथ दो वीडियो कॉंफ्रेंस आयोजित की गई थी और यह सूचना दी गई है कि अमरावती की पायलट परियोजनाएँ जीएसडीए और सीईओ-जिला परिषद स्तर के बीच विभिन्न मुद्दों के कारण रुक गई हैं।

यह बात आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पिछले वर्ष तक प्रगति की दृष्टि से महाराष्ट्र के पायलट ब्लॉक (वरुड और मोर्शी) अग्रणी ब्लॉकों में से एक हैं। तथापि, पिछले वर्ष से जीएसडीए से खराब समन्वयन और गैर जिम्मेदाराना रवैया की वजह से कार्यान्वयन की गति प्रभावित हुई है।

वीसी के दौरान जो मुद्दे सामने आएँ और जिन्हें तत्काल पूरा करने की आवश्यकता है वे निम्नानुसार हैं:-

1. राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) की नियुक्ति:

किसी भी राज्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। जिला नोडल अधिकारी को एसएनओं का प्रभार सौंपा गया है। सुझाव है कि उपयुक्त एसएनओ तत्काल नियुक्त करें।

2. जीएसडीए:

वीडियो कॉंफ्रेंस (30-10-2014 को आयोजित) के दौरान यह ज्ञात हुआ कि पायलट परियोजना में जीएसडीए की भूमिका को मात्र तकनीकी सहायता तक ही संकुचित करना चाहिए। पायलट परियोजना कार्य के लिए वित्त संबंधित मुद्दों और प्रशासनिक कार्य से संबंधित निर्णय राज्य विभागों द्वारा लिए जाएँ उन्हें जीएसडीए पर न छोड़ा जाए। यह नोट किया जाए कि वीडियो कॉंफ्रेंस में जीएसडीए के साथ मुद्दे पर चर्चा और जीएसडीए को (दिनांक 08-08-2014) पत्र भेजने के बावजूद इस मंत्रालय को कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

3. सहायता संगठनों को जारी की गई निधियाँ:

वीसी में यह ज्ञात हुआ कि सहायता संगठन को निधियाँ जारी न करने की वजह से एस.ओ. के प्रशिक्षित मानव बल ने कार्य छोड़ दिया है जिससे परियोजना कार्यों में आगे की प्रगति रुक गई है।

4. ग्राम जल सुरक्षा योजना (वीडब्ल्यूएसपी) का अनुमोदन:

वीसी में यह सूचना दी गई है कि 16 ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार की गई है जिन्हें मंत्रालय को भेजने से पूर्व पीएसडीए से अनुमोदन प्राप्त होना शेष है। तथापि जीएसडीए ने यह बताया है कि उन्हें अब तक कोई भी वीडब्ल्यूएसपी प्राप्त नहीं हुई है। अत: जीएसडीए को निर्देश दिया जाता है कि वे तैयार की गई वीडब्ल्यूएसपी की जाँच करें और कम से कम एक वीडब्ल्यूएसपी परीक्षण हेतु यथाशीघ्र इस मंत्रालय को भेजा जाए।

5. वर्षा मापी की प्राप्ति और उसकी संस्थापना:

जीएसडीए अधिकारियों ने यह सूचना दी है कि जिला परिषद (वर्षा मापी की प्राप्ति और जल स्तर सूचकांकों) के लिए उल्लिखित दर बहुत अधिक है। जीएसडीए को यह सुझाव दिया गया है कि वे आवश्यक उपकरण जीएसडीए से ब्लॉकों तक पहुँचाएँ। जीएसडीए से उत्तर प्राप्त होना शेष है।

यह महसूस किया गया है कि इन मुद्दों को निपटाने के लिए आपका मध्यावर्तन आवश्यक है। जीएसडीए की भूमिका को संशोधित करना आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार का विलंब न हो।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से भी एक प्रतिनिधि पायलट ब्लॉकों के दौरे के लिए भेजा जाएगा ताकि अब तक की प्रगति और किए गए कार्यों का मूल्यांकन हो सके।

अत: आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई के लिए संबद्ध अधिकारियों को निर्देश दें। गैर-जिम्मेदारी की स्थिति में मंत्रालय राज्य को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सुरक्षा पायलट परियोजना से हटा सकता है।

भवदीय,

(सत्यब्रत साहु)

श्री राजेश कुमार
प्रधान सचिव,
ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता,
जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग,
गोकुलदास तेजपाल अस्पताल, न्यू बिल्डिंग, 7वाँ तल,
एस टी मार्ग, न्यू क्राफोर्ड मार्किट,
मुम्बई
महाराष्ट्र -400 002

प्रति:

1. श्री रुपेश सिंह, आईएएस, निदेशक, जीएसडीए; कृषि विश्वविद्यालय कैंपस, वाकदेवाड़ी रोड, शिवाजीनगर, पुणे-411005
2. श्री बी.के. सवई, निदशक, डब्ल्यूएएसएसओ जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग, जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन, सीडको भवन (साउथ विंग) पहला तल, सीबीडी बेलापुर, नवीं मुम्बई, महाराष्ट्र-400614
3. श्री अनिल भंडारी, सीईओ-जिला परिषद; मुख्य अभियंता कार्यालय जिला परिषद, अमरावती, कोर्ट कैंप जिला परिषद के समीप, अमरावती
4. सुश्री श्वेता बैनर्जी, जिला नोडल अधिकार-पायलट परियोजनाएँ (अमरावती); कोर्ट कैंप जिला परिषद के समीप, अमरावती

(सत्यब्रत साहु)

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी वेबसाइट पर डालने हेतु

W-11042/16/2010-Water-II
Government of India
Ministry of Drinking Water & Sanitation
***

9th Floor Paryavaran Bhavan,
CGO Complex, New Delhi-110003
Dated: 08-08-2014

To,
Director
Groundwater Surveys and Development Agency (GSDA),
Agriculture College Campus, Wakdewadi Road, Shivajinagar, Pune – 411 005,
Maharashtra
(Fax no. 022-22621791)

Subject: National Rural Drinking Water Security Pilot Projects

Ref.:

1. Lr. No. 1015/2014, Dt. 08-07-2014;
2. Lr. No. 67/2014 Dt. 07/07/2014;
3. Lr. No.393/2014 Dt. 04-07-2014;
4. Lr. No.1367/2014, Dt. 27-05-2014;
5. Lr. No. O. No./RWSD/IEC/1341/2014, Dt. 19-05-2014;
6. Lr. No. 765/2014, Dt. 10/3/2014

Sir,

As you are aware, the Ministry of Drinking Water and Sanitation is implementing through the States the National Drinking Water Security Pilot Projects in which block-wise water security plans are being prepared in 15 over-exploited/critical blocks in 11 different States. Warud and Morshi Blocks from District Amravati were also a part of this immensely important Pilot Project.

A Video-conference for review of progress of Pilot Projects was held with 11 States on 30-07-14, chaired by the Joint Secretary (Water), MDWS (copy of minutes enclosed). It was observed that the progress of works/activities in both blocks of Amravati district is going on a slow pace because of various reasons/issues.

During the VC, the State Nodal Officer was directed to send a copy of all the communications sent to GSDA, pertaining to the issues related to pilot projects, to the Ministry (Reference letters enclosed).

It was also learnt that there are various pending activities, which are yet to be approved by Groundwater Surveys and Development Agency (GSDA). The main of these are:

Section Officer
11/8/14

1. **Renewal of contract of the SO as per the work to be completed:**
   GSDA has to submit an evaluation report of the work done by the SO, to the Ministry. Further, a communication has to be sent to the Ministry about the contract renewal with the SO.

2. **Fund release to the Support Organisation (SO) as per the work completed:**
   It is suggested to take necessary action for releasing the payment to the SO as per the work completed by them.

3. **Approval of Village Water Security Plans (VWSPs) already prepared:**
   It was reported in the VC that about 16 village water security plans are prepared, but none of them was cleared by GSDA. It is, therefore, requested to scrutiny the VWSPs prepared so far, and send at least one or two samples of VWSP for further examination and approval of model plan to this Ministry at the earliest.

4. **Procurement and installation of rain gauges:**
   It is suggested to felicitate the works pertaining to the procurements and installations, as the delay in these activities are hampering the overall progress of the Pilot projects, and accordingly action may be taken for releasing the payments.

It is strongly felt that your intervention is required to get the issues sorted out at the earliest. Further, a representative from Ministry of Drinking Water and Sanitation will be deputed to visit the Pilot Blocks in month of September, for action taken reporting on the points highlighted during the review in the Video-conference and the request made herein to GSDA for sorting out the pending issues.

You are therefore requested to direct the concerned officials to take immediate action on the issues listed above. The outcome of this project would go a long way in the success of this pilot project on Over-exploited blocks so as to ensure Drinking Water Security to rural people.

Yours faithfully,

[Dr. Dinesh Chand]
Addl. Adviser (PHE)
Tel- 011-2436660

Copy to:

1. Principal Secretary, Rural Water Supply and Sanitation, Govt. of Maharashtra, 7th Floor, G. T. Hospital premises, New Mantralaya, Mumbai 400 001 (Fax-020-22622084)
2. Chief Engineer, Rural Water Supply and Sanitation, 7th Floor, G.T. Hospital Premises, New Mantralaya, Mumbai-01
3. CEO- Zila Parishad, Zila Parishad Camp Road, Amravati-444602
4. Director-WSSO, SIDKO Bhavan South Wing First Floor, CBD. Belapur-444602
5. State Nodal Officer- Pilot Projects , Amravati